that there is a Committee which has recommended that they would not be given a Permanent Commission—are they going to relax it and going to make the Short Service Commission as Permanent Commission?

SHRl A.K. ANTONY: I have already assured the House when Brindaji asked her question. Even though under the present policy there is no Permanent Commission to the women, but as per the requests from various quarters mainly from women organisations and also Members of Parliament Unanimously, cutting across party lines, 1 assure the House that we will reexamine the case an we will try our best to find a solution.

DR. K. MALAISAMY: Thank you, Mr. Chairman, Sir. It is a general consensus of this House that though according to the law, as per the reply of the Minister and as per the presentation of the Minister, there is no discrimination, but the ground reality is that there is discrimination. That is how we look at it. In such situtation, what are all the measures that can be taken? How could you do that when in reality there is discrimination? Under the law, it may not be there.

SHRI M.M. PALLAM RAJU: Sir, when the Short Service Commission was started, it was both for men and women and based on their ACRs, performance and based on the needs, the Armed Forces did induct a few of the men. Subsequently, in 2006, based on the recommendation of a Committee which was headed by the Headquarters of the Integrated Defence Staff, a decision was taken that no Short Service Commission officers either men or women would be taken into the Services. So. subsequent to that there is no question of any discrimination.

घुसपैठ के संभावित खतरे

*182. **डा0 प्रभा ठाकुर**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत दो वर्षो के दौरान देश की विभिन्न सीमाओं पर सीमा पार के विदेशी घुसपैठियों द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में की जा रही घुसपैठ के मामलों में कमी आई है;

(ख) पड़ोसी राज्यों से आने वाले ऐसे घुसपैठियों से किस-किस प्रकार के खतरे संभावित है;

(ग) सरकार ने ऐसी घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए क्या उपाय किये है;

(घ) ये उपाय कितने कारगर सिद्व हुए है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वी0 पाटिल): (क) से (ड) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) और (ख) विदेशी घुसपैठियों आदि की आंशका के बारे में उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि भारत- पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पार से होने वाली घुसपैठ में गिरावट आई है। सीमाओं पर विदेशियों द्वारा सीमा- पार से घुसपैठ किए जाने की कोई बढी घटना घटित नहीं हुई है। हालांकि देश में अवैध आग्रवासन के कई सामाजिक आर्थिक निहितार्थ है,परन्तु विदेशी घुसपैठियों से मुख्य खतरा उनका आतंकवादी /विध्वंसक गातिविधियों में संभावित संलिप्तता है।

(ग) से (ड) सरकार ने विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा सीमा-पार से घुसपैठ किए जाने को रोकने के लिए बहु- आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गश्त लगा करके और निगरानी चौकियां स्थापित करके सीमा की

चौबिसों घंटे निगरानी करना; सीमा पर बाड़ का निर्माण करना और तेज रोशनी करना; आधुनिकी और उच्च प्रौद्योगिकी के निगरानी उपकरण लगाना; आसूचना व्यवस्था का उन्नयन करना और राज्य सरकारों तथा संबंधित आसूचना एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना शामिल है। इन उपायों के पारिणामस्वरूप सीमापार से घुसपैठ में कमी होने की प्रवृत्ति हुई है। विगत तीन वर्षों के दौरान भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा विदेशी घुसपैठियों की आशंका का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	भारत-पाकिस्तान सीमा	भारत-बांग्लादेश सीमा	कुल
2005	202	6384	6586
2006	128	5130	5258
2007	128	4206	4334

Possible dangers due to intrusion

t*182. DR. PRABHA THAKUR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is a decrease in the intrusion in various States by the foreign intruders on the various borders of the country during the last two years;

(b) the details of the possible dangers that might occur from such intruders coming from the neighbouring countries;

(c) the measures taken by Government to curb such intrusion;

(d) the extent of effectiveness of these measures; and

(e) the details thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Available information about apprehension of foreign intruders, etc., indicates a decline in cross-border infiltration on the Indo-Pakistan and Indo-Bangladesh borders. There * is no significant incidence of cross-border intrusion of foreigners on the other borders. While illegal immigration into the country has various socio-economic implications, the dangers* from foreign infiltration relates mainly to their likely indulgence in subversive/terrorist , activities.

(c) to (e) The Government have adopted a multi-pronged approach to contain cross-border intrusions by foreign nationals which, *inter-alia,* includes round the clock surveillance & patrolling on the borders and establishment of observation posts; construction of border fencing and flood lighting; introduction of modern and hi-tech surveillance equipment; upgradation of intelligence set up and coordination with the State Governments and concerned intelligence agencies. As a result of these measures, cross-border intrusion has shown a declining trend. The details of apprehensions of foreign intruders made by Border Security

tOnginal notice of the question was received in Hindi

Force on Indo-Pakistan and Indo-Bangladesh International Borders during the last three years are as under:

Year	Indo-Pakistan Border	Indo-Bangladesh Border	Total
2005	202	6384	6586
2006	128	5130	5258
2007	128	4206	4334

डा0 प्रभा ठाकुर: महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी की ओर से जो जवाब आया है, उसमें लिखा है कि भारत-पाकिस्तान और भारत- बांग्लादेश की सीमाओं पर सीमा पार से होने वाली घुसपैठ में गिरावट आई है और उसके आंकड़े भी दिए हैं। अगर मैं इन आंकड़ों को देखूं तो मुझे लगता है कि हां, घुसपैठ में कुछ कमी हुई है। ये आंकड़े किस प्रकार संकलित किए जाते हैं, क्या ये राज्य सरकारों द्वारा भेजे जाते हैं या केन्द्र सरकार सीधे इनको संकलित करती है? इसमें नेपाल की सीमा से भारत में घुसपैठ संबंधी आंकड़े नहीं दिए गए हैं, यह एक गंभीर समस्या है।

महोदय, इसमें सरकार ने घुसपैठ को रोकने के लिए जो उपाय किए हैं...उसमें निगरानी, बाड़ निर्माण, तेज रोशनी की व्यवस्था, आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी उपकरण , लेकिन इसके अतिरिक्त मुझे लगता है कि पर्याप्त नहीं हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यक यह है कि जो संबंधित अधिकारी हैं, चौकसी पर या जो सुरक्षा बल हैं या जिनकी जवाबदेही है, उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी सुनिश्चित करना कि उनके होते हुए, इस पूरी व्यवस्था के होते हुए कैसे सीमा पार से घुसपैठ जारी है, क्योंकि जब यह घुसपैठ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप सवाल पूछ लें।

डा0 प्रभा ठाकुर: जी, मैं यही पूछ रही हूं कि घुसपैठ है, तो इसका अर्थ ही यही है कि वह अवैध है, तो अवश्य अवैध कार्यों के लिए है और महोदय, उन अवैध कार्यो के परिणामस्वरूप घातक ड्रग्ज़ का भारत में आना, अवैध हथियारों की सप्लाई और आतंकवाद को प्रोत्साहन, इसका परिणाम देश की मासूम जनता भुगतती है और लोग हिंसा के शिकार होते हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please put the question.

डा0 प्रभा ठाकुर : कई बार राजनीतिक दल उसका इस रूप में लाभ उठाते हैं कि ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please put the question.

डा0 प्रभा ठाकुर: यहां के स्थानीय लोगों द्वारा ऐसा किया जा रहा है और समुदाय की बात आती है, जबकि वह विदेशी घुसपैठियों द्वारा किया जाता है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, this is not an occasion for making statements.

डा0 प्रभा ठाकुर: मैं यह जानना चाहती हूं ...(**व्यवधान**)... महोदय, मैं अपनी बात पर आ रही हूं, मैं इसका संदर्भ देते हुए, अपनी बात कहना चाहती हूं कि क्या गृह मंत्री जी यह महसूस करते हैं कि अभी तक जो उपाय हैं, वे पर्याप्त हैं या इससे अधिक कोई कठोर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह निश्चित है कि इससे वे भारत में रहने वाले लोगों को बदनाम करते हैं। आते हैं घुसपैठिए और कार्रवाई उनकी होती है। माओवाद हो, नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो या ड्रग्ज़ वगैरह हो, तो उनको रोकने केलिए और कठोर कारगर उपाय उठाएं।

एक बात मैं और बताना चाहती हूं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप सवाल पूछ लें,

डा0 प्रभा ठाकुर: एक बात और महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है। अभी पश्चिमी राजस्थान सीमा पर सौ बीघा ज़मीन विदेशी कंपनियों ने खरीदी है लैंड बैंक बनाने के नाम पर, जो कि बॉर्डर पर है, इससे भी घुसपैठ को प्रोत्साहन ही मिलने की संभावना है। माननीय गृह मंत्री जी, मैं यह भी कहूंगी कि इस बारे में भी वे राज्य सरकार से जानकारी करें और इसका पूरा विवरण लें कि ऐसा क्यों हुआ और आगे इस घुसपैठ पर और कड़ाई से सख्त कदम उठाने के लिए वे क्या कार्यवाही करना चाहेंगे, यह मैं उनसे जानना चाहूंगी।

MR. CHAIRMAN: Before the hon. Minister replies, I would like to make it clear to the House that the questions have to be questions. They cannot be statements. If the need arises.' the Chair will disallow.

श्री शिवराज वी0 पाटिल: नेपाल और भारत की सीमा मुक्त सीमा है, इसलिए नेपाल से यहां जो आते हैं और यहां से नेपाल जाते हैं, उनको अपने साथ कोई कागज़ पर परमिशन लेकर आने-जाने की जरूरत नहीं है। जहां तक हमारी यह सीमा है, यह ध्यान में रखना जरूरी है कि वह पंद्रह हजार किलोमीटर की सीमा है और अलग-अलग प्रकार की सीमा है। कहीं पहाडी इलाका है, तो कहीं रेगिस्तान है, कहीं ऐसे इलाके है जहां पर पानी है और नदी का पानी है , riverine areas हैं, आसानी से वहां पर बाड़ लगाना भी मुश्किल है । सरकार की तरफ से यह कोशिश है कि हमारे जो बल हैं, सीमा सुरक्षा बल हैं, जो अलग –अलग नामों से सीमा पर काम कर रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ाए और जो हमारे बॉर्डर आउट-पोस्ट्स हैं, उनकी संख्या बढ़ाए और दो बॉर्डर आउट-पोस्ट्स के बीच में जो जगह है, उसको कम करें, जो electronic equipments है, उनके द्वारा वे काम करें और जो Intelligence agencies हैं, उनको strengthen करेक यह करें। जो काम आज हो रहा है, उसके मुताबिक आंकड़े यहां पर दिये गए हैं। किसी भी काम में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, इसमें भी इंप्रूवमेंट जहां तक करना जरूरी है, वह किया जाएगा।

डा0 प्रभा ठाकुर: सर, सीमा सुरक्षा बल की मौजूदगी में अगर घुसपैठ जारी रहती है, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई हुई है या नहीं, यह मैं जानना चाहती हूं, चाहे उन्हें suspend करना हो, चाहे उन्हें कुछ साल के लिए बाहर रखना हो, किसी तरह की कार्रवाई हुई है या नहीं? जब तक यह नहीं होगी, तब तक घुसपैठ जारी रहेगी, तो इस बारे में माननीय गृह मंत्री जी का क्या कहना है?

श्री शिवराज वी0 पाटिल: श्रीमन् इस बारे में यह ध्यान में रखना जरूरी है कि दो बॉर्डर आउटपोस्ट्स के बीच का जो फासला है, वह साढ़े तीन किलोमीटर का होता है। एक जगह पोस्ट है और वहां पर लोग है व साढ़े तीन किलोमीटर बीच काजो एरिया है, वहां पर कोई आदमी खड़ा हुआ नहीं है। पेट्रोलिंग जरूर होती है। ऐसे जो बॉर्डर हैं, जहां पर फेंस लगायी गयी है, मसलन पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बॉर्डर पर फेंस लगायी गयी है, वहां पर जो घुसपैठियों की संख्या है, वह कम होगी। बंग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर फेंस लगायी गयी है लेकिन पूरी जगह पर नहीं है, riverine एशिया वहां पर ज्यादा है इसलिए वहां पर उनकी संख्या ज्यादा है। लेकिन, भूटान, नेपाल या तिब्बत-जहां पर बॉड्र्स पर फेंस नहीं लगायी गयी है, म्यांमार में नहीं लगायी गयी है, वहां पर कोई फेंस नहीं है। वहां पर रात-दिन बर्फीले एरिया में, रेगिस्तनी एरिया में जिनको महीनों से अकेला रहना पड़ता है। कोई इधर-उधर से आता है, उनको आने-जाने की परवनगी भी दी गयी है, उसके ऊपर कार्यवाही की जाए-अगर ऐसा कहा जाए, तो ठीक नहीं है। अगर किसी ने किया है, विद डिज़ाइन किया है तो जरूर कार्यवाही की जाएगी लेकिन यह सारी चीजें ध्यान में रखकर ही कार्यवाही करना या न करना उचित होगा।

SHRI EKANATH K. THAKUR: Thank you, Sir. The numbers for the last three years have been given. Sir, through your good self, I would like to know from the hon. Minister the total number of intruders who have entered India and are staying in India right from 1947 to date. There are two types of intruders. One is those who come for reasons of economic livelihood and opportunity. Then, there are those who come for terrorist purposes. I would like to know whether the camps of the terrorists in adjoining countries have been identified. How many of them are there? And, what is the Government of India doing in terms of the training that is being given to terrorists there and being sent here. Is there any proposal to deal with those terrorist camps which are in the adjoining/neighbouring countries?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, the information which is available with me about the infiltrators in India up to this time is that nearly 80,000 people had infiltrated. Then, they have been deported also; sent back also. So, this is the broad information which is available with us. ...*(Interruptions)...*

SHRI EKANATH K. THAKUR: Infiltration from Bangladesh is more than one crore. *(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Let the hon. Minister reply. ...*(Interruptions)*...

SHRI EKANATH K. THAKUR: This same Government had earlier given this information.

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, as far as the training camps in the neighbouring countries are concerned. This matter is taken up in the committee in which the Home Secretaries of the concerned Governments meet very often. We hold committee meetings. A committee meets - with the officers of Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Nepal, and Bhutan every year. These matters are discussed there.

As far as the matter regarding training camps in neighbouring countries is concerned, these matters are also discussed. We are told that there are no training camps, and when the information is given, we are told that necessary action would be taken. Now that is the kind of diplomacy which is going on. That is the kind of efforts we are doing. But, as far as other countries are concerned, we have some limitations under which we have to work and we have to keep that in mind.

DR. V. MAITREYAN: Thank you very much. Sir. The problem is, for the Union Government, whether it is the UPA or the NDA, border always means land borders and infiltration always means only from Pakistan and Bangladesh. They conveniently forget the sea border. The ground reality and prevailing situation in Tamil Nadu is swept under the carpet. I would like to know this from the hon. Home Minister. Does he have figures about the LTTE infiltration into Tamil Nadu? How many have been arrested? How many cases have been booked? And, what action has the Central Government taken on these?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, it is true that border does not means only land border. It means sea border also. Whereas we have 15,000 kilometres of land border, we have, nearly, 7000 kilometres of sea border. It is true that infiltration through sea route is also taking place. When we put fence on the borders, people try to enter the country through the sea route. That fact is kept in mind. As far as providing security on the sea border is concerned, the Navy helps and the Coast Guard also helps. And, the State Police also has to take the action. We have also now created the 'coastal police stations' and we have given funds to the State Government to establish the 'coastal police stations' and recruit policemen who can cooperate with the Coast Guard and the Navy in order to stop the infiltration from other countries. As far as the exact figure about that is concerned, I would supply it to the hon. Member..

MS. MABEL REBELLO: Sir, the Myanmar citizens come to Mizoram, to Aizawal very often. They come especially with their animals, with cows, with pigs, and with drugs also, and, when they come, they walk on the National Highway. I have seen it myself very often. On both the sides, there are Mizos. On the Indian side and on the other side also, there are Mizos. I would like to know from the hon. Minister whether it is a good way of building people-to-people contract, which we are trying to build up so that nobody is ever caught, nobody is averse and nobody says anything to them. Is Government purposely doing it, encouraging them to come to this side and do trade and commerce with the Indian community? **Sir,** this is what I would like to know.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, it is a fact that on border between Myanmar and India, up to 20 kilometres on Myanmar side and 20 kilometres on Indian side, the citizens are allowed to come and go. ...*(Interruptions)*...

MS. MABEL REBELLO: Sir, it is not 12 kilometres. It is almost 100-150 kilometres. That is what I know. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please allow the answer to proceed.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: So, this is the area in which they are allowed because these are the areas where the roads are not constructed and the people living in the forest areas belong to families and relations and all those things. So, both the Government have decided that up to 40 kilometres on the borders, free access will be allowed. But if they come beyond 40 kilometres, then, it is possible and it is necessary to take action against them if they are coming without permission. But these are the areas where the population is very sparsely located and it is not infiltration that is taking place on these borders because the population is very limited. It is also very low. Here and there, instances of people coming from one side to the other side may be there and it is also very difficult to recognise them because there are a lot of similarities, facial similarities and the language similarities and all those things. Now, this is the situation in which the border forces are working.

MR. CHAIRMAN: Question No. 183. ...*(Interruptions)*...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: सर, हम प्रश्न पूछने के लिए बहुत पहले से हाथ उठा रहे हैं। ....(**व्यवधान**).

MR. CHAIRMAN: See, I have to follow the established procedures. ...*(Interruptions)*...

श्री कलराज मिश्र: सर, मैं सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाहता हूं। ....(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: We will come to you. ...*(Interruptions)*... Q. No. 183.

Low Investment in R & D

♦**183.** SHRI N.R. GOVINDARAJAR: Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(च) whether investment in Research and Development in Science and Technology in India remains below the required level as compared to the other developing countries;

(छ) whether Government proposes to liberalize Research and Development system to enhance scientific activities in the country;

(ज) whether Government has submitted any plan for Research and Development in Science and Technology to the Planning Commission; and

(झ) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Acording to the available official statistics, the expenditure on Research and Development (R & D) as percentage of Gross Domestic Product (GDP) in India is lower compared to that of a few developing countries like Brazil and China, but it is higher compared to several developing countries like Argentina, Cuba, Sri Lanka and Paksitan as given in the Statement-I *(See* below)